सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 5/2022

दिनांक : 01/05/2021

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

विषय : मई दिवस अमर रहे ।

मई दिवस 2022 के अवसर पर देश दुनियां के तमाम मेहनतकश वर्ग के साथ-साथ हम मध्यक्षेत्र के समस्त बीमाकर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

मई दिवस को महज औपचारिकता के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि आज से ठीक 133 वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो शहर में जब मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, तब साम्राज्यवादी, दमनकारी, मजदूरों को इंसान न समझने वाली, मजदूरों का शोषण कर 'मुनाफा' को लक्ष्य करने वाली अमरीकी साम्राज्यवाद ने, आंदोलनरत श्रमिकों के ऊपर गोलियों की बारिश कर तीन मजदूरों की हत्या कर दी थी और इन्हीं मजदूर नेताओं को फांसी दे दी थी। शहीदों की याद में 'मई दिवस' प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में शोषण, अत्याचार, दमन के खिलाफ शोषणविहीन समाज के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा के रूप में दुनिया भर के श्रमिक वर्ग द्वारा बदस्तूर उत्सवित किया जाता है। अगर हम 133 वर्ष पहले की स्थिति पर नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि इन वर्षों में मजदूरों की स्थिति में कुछ परिवर्तन तो जरूर आया है लेकिन शोषण और दमन की पूंजीवादी आक्रामकता और श्रमिक विरोधी नीति आज भी जारी है, भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो मगर यह सिलसिला जारी है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति और भयावह है। पूरी दुनिया में जारी आर्थिक मंदी, करोना के दौर में पूंजीवादी दुनिया की अमानवीयता की तस्वीर, आपदा के दौरान श्रमिकों के सामाजिक लाभों पर हमले दूसरी ओर चंद लोगों के हाथों विश्व जनता की संपत्ति के बढ़ते केंद्रीयकरण इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं। मई दिवस विश्व के श्रमिक वर्ग को इन हालातों के लिए जिम्मेवार ताकतों के खिलाफ दुनिया के श्रमिकों के संघर्ष को सुदृढ़ करने और एक बेहतर समाज निर्माण के प्रति समर्पण के लिए प्ररित करता है।

आज देश की स्थिति पर चर्चा करें तो हम क्या देखते हैं, हर तरफ, हर वर्ग में, चाहे वह मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान, छात्र, नौजवान व गृहिणी, जबर्दस्त असंतोष का माहौल है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा की सरकार की जनविरोधी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के चलते देश में अराजगकता की स्थिति निर्मित हो रही है। अर्थव्यवस्था का कचूमर निकला जा रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, महंगाई ने गरीब से लेकर मध्यम वर्ग को त्रस्त एवं पस्त कर रखा है। इन ज्वलंत मुद्दों को गंभीरता से सुलझाने के बजाए इसे उलझाने के लिए तथा आम जनता को भ्रमित करने के लिए, मंदिर मस्जिद, हिजाब, लाऊड स्पीकर, इत्यादि जैसे सांप्रदायिक मुद्दे को उछालकर लोगों को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि इन सांप्रदायिक एजेण्डा से जो केवल और केवल चुनावी सफलता के लिए ध्रुवीकरण का एक कुत्सित प्रयास मात्र है। आज समय है कि देश को बांटने वाली, कमजोर करने वाली, किसी भी एजेण्डे के खिलाफ देश के तमाम मजदूर, किसान, छात्र, महिला एवं बुद्धिजीवियों को अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए जनता के बीच सड़क पर जाना होगा और देश को बचाना होगा।

वैश्विक स्तर पर अगर बीते वर्षों में हम नजर डालें तो पाते हैं कि दुनिया भर में उथल-पुथल का दौर चल रहा है, ताजा उदाहरण यूक्रेन-रूस के बीच का युद्ध है। इस युद्ध से एक बार फिर 'विश्वयुद्ध' की ओर ले जाने का कयास लगाया जा रहा है। इस युद्ध ने रूस को, अमेरिका सहित जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि से अलग-थलग करने की कोशिश की गई। हमने सदा ही कहा है कि यह युद्ध

बंद होना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है किंतु इस युद्ध की जड़ में भी अमरीकी साम्राज्यवाद ही है। सोवियत यूनियन के पराभव के बाद नाटो के मामले में विश्व को दिए वचनों के विपरीत नाटो के जरिए अपने महत्वाकांक्षी विस्तारवाद लिए उसने विश्व पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने का जो एजेण्डा चलाया है यही उसी की देन है। दूसरा, अमरीकी साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा उद्योग हथियार उद्योग ही है और इस उद्योग का लाभ दुनिया में अशांति से गहरे से जुड़ा है। यूक्रेन को दी जा रही सामरिक मदद कौन कर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह घटनाक्रम विश्व शांति के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है हालांकि पूरी दुनिया में इस दक्षिण पंथी विचार के बावजूद उतना ही इन तानाशाही, विस्तारवादी और साम्राज्यवादी सोच का विरोध दुनिया के हर हिस्से में हो भी रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लातिन अमरीकी देशों के घटनाक्रम इसी तथ्य की पुष्टि करता है।'

बीमा उद्योग पर चर्चा करें तो एक बात स्पष्ट है कि वर्तमान भाजपा की केंद्र सरकार इस उद्योग को गर्त में डालने का बीड़ा उठा चुकी है। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अपने कार्यकाल में संसद के अंदर अपने बयान में कहा था कि 'पब्लिक सेक्टर तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं।' फिर इनसे और इनकी सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम को सुरक्षित रखने और बचाने की उम्मीदें करना ही बेमानी है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाईपलाइन के जरिये देश की तमाम सार्वजनिक संपत्तियों की नीलामी, कृषि क्षेत्र को कार्पोरेट के हवाले करने बाये गये कृषि कानून, देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को निजी देशी-विदेशी पूंजी के लिए खोने की उनकी मुहिम इस सरकार के चरम दरबारी पूंजीवादी रुख के ही उदाहरण हैं। करोना अवधि में यह सब आपदा को अवसर में बदलने के नाम पर किया जा रहा है। यह अवसर किसके लिए है, यह किसी से छिपा नहीं है। फोर्ब्स की हालिया सूची में भारत का कौन व्यक्ति विश्व के सबसे शीर्ष धनिकों की सूची में पांचवा स्थान प्राप्त कर लिया और एशिया के सबसे धनिकों की श्रेणी में किसने पहला स्थाना प्राप्त कर लिया, यह सब सभी को सर्वविदित है। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री की आधिकारिक भारत यात्रा की शुरुआत कहां से हुई और वे किससे द्विपक्षीय चर्चा से यात्रा की शुरुआत किए, आप सभी उससे अवगत हैं। एक ओर महंगाई, दरिद्रता, भुखमरी, बेरोजगारी का चरम पर पहुंचना और गौतम अदानी का धनिकों के ऊंचे पायदान पर पहुंचना बढ़ती असमानता के भयावहता और इस सरकार की नीतियों के खोखले दावों की हकीकत को स्वयं ही बयां करता है। सरकार की नीतियों के खिलाफ चौतरफा प्रतिरोध भी तीव्र हुआ है। एक साल से अधिक समय तक चले अभूतपूर्व किसान आंदोलन ने अंततः सरकार को कृषि कानून पर कदम पीछे करने बाध्य किया। इन्हीं सब परिस्थिति में देश के अंदर 28-29 मार्च 2022 की ऐतिहासिक हड़ताल ने सिद्ध किया कि देश की जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान बीमा उद्योग के साथ साथ अन्य सार्वजनिक उद्योगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकृत करने के लिए भारत सरकार आईपीओ लाने जा रही है जिसका विरोध बीमा कर्मचारियों एवं देश के अन्य श्रमिक संगठनों, विपक्षी राजनैतिक दलों, अर्थशास्त्रियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस विरोध को अनदेखा कर सरकार के पूर्व के घोषित 5 प्रतिशत की बजाय 3.5 प्रतिशत शेयर की बिक्री का ऐलान कर दिया है। 4 मई को आईपीओ के खुलने की घोषणा कर दी गई है। शर्मनाक तथ्य यह है कि सरकार न केवल एलआईसी जैसी वित्तीय संस्थान के पूर्व के मूल्यांकन को घटा दिया बल्कि शेयर के मूल्य के संभावित मूल्य से कहीं कम मूल्य पर इसकी बिक्री की घोषणा की है। यह कुछ और नहीं बीमाधारकों और बीमा उद्योग के कार्यबल के योगदान से संचित की गई विपुल संपदा को कौड़ियों के मोल अपने कार्पोरेट आकाओं को सौंपने का महाभ्रष्टाचार है। एआईआईईए इसके खिलाफ देश के सभी बीमाकर्मियों से 4 मई को ही दो घंटे की बहिर्गमन हड़ताल के जरिए जोरदार प्रतिकार करने का आव्हान किया है। विगत 3 दशकों से राष्ट्रीयकृत एलआईसी को बचाने की यह लड़ाई निश्चय ही आगामी दिनों में और तीखी होगी।

अंत में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सकारात्मक सोच के साथ कि संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को हासिल कियाजा सकता है, रास्ते में कांटे भले ही हों, इसकी चुभन को सहते हुए रास्ता तय करना ही होगा, इस विश्वास के साथ कि अंतिम विजय हमारी यानि मजदूर वर्ग की ही होगी।

एक बार पुनः मई दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई...

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ...

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव